टी. एन. सेशान, भारत ई. टी. सी. के प्रमुख चुनाव आयोग।

वी.

भारत और अन्य का संघ

14 जुलाई, 1995

[ए. एम. अहमदी, सी. जे., जे. एस. वर्मा एन. पी. सिंह, एस. पी. बरुचा और एम. के. मुखर्जी, जे. जे.]

भारत का संविधानः कला का खंड (1)। 123 .

अध्यादेश की घोषणा-भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग-अध्यादेश (1993 का संख्या 32) जिसका शीर्षक है "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (कोंडी)

सेवा के राज्य) संशोधन अध्यादेश 1993 ", मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त (सेवा की शर्त) अधिनियम 1991 में कुछ प्रावधानों को संशोधित, प्रतिस्थापित और जोड़ा गया-मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तों का निर्धारण करना और चुनाव आयोग द्वारा कार्य के लेन-देन की प्रक्रिया और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करना। वहाँ तक।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 324।

निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद के तहत शक्तियों के प्रयोग में निहित होना। 324 (2) , भारत के संविधान का-सीईसी के अलावा चुनाव आयुक्त की संख्या दो निर्धारित की गई थी-बाद की अधिसूचना द्वारा, दो ईसी नियुक्त किए गए थे-अध्यादेश की वैधता, अधिसूचनाएं और परिणामी आदेश और नियुक्तियां-- चाहे संविधान मनमाना हो या अधिकार से बाहर।

अनुच्छेद 324 के खंड 2 की व्याख्या-क्या एक बहु सदस्यीय चुनाव आयोग की परिकल्पना की गई है। सीईसी और अन्य ईसी के बीच अंतर - चाहे अनिवार्य रूप से उनके कार्यकाल के कारण-अध्यादेश के आधार पर, सी. ई. सी. और ई. सी. को वेतन आदि के मामले में बराबर रखा जाता है।

अनुच्छेद के खंड (5) का पहला परंतुक। 324 - क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को जिस प्रकार की हटाने की योग्यता प्रदान की गई है, वह अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में उन्हें उच्च दर्जा प्रदान करने का संकेत है।

106 T.N.SESHAN v. यू. ओ. आई.

107

एक बहु-सदस्य निकाय में-क्या मुख्य चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त के कार्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य है या मुख्य चुनाव आयुक्त में अनन्य निर्णय लेने की शक्ति का केवल सलाहकार विचार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए अनुकूल नहीं है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त

(सेवा की शर्त) अध्यादेश, (अब अधिनियम) 1993।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव का अध्याय III

आयुक्त (सेवा की शर्त) अधिनियम, 1993,-सेक। 9 , 10 - विधायी क्षमता का सवाल-अनुच्छेद 324 का खंड 2 और 5, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों के लिए एक क़ानून पर विचार करता है और स्पष्ट रूप से प्रदान करता है-इसलिए उस प्रभाव के प्रावधानों को असंवैधानिक के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति-चाहे वह मुख्य चुनाव आयुक्त के न्यायाधीश के समान हो।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय-वरीयता के वारंट में मुख्य चुनाव आयोग की स्थिति-चाहे पुनर्विचार की आवश्यकता हो, सरकार को समानता प्रदान नहीं करनी चाहिए या वरीयता के वारंट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यदि इससे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति प्रभावित होने की संभावना है, हालांकि मांग पर जोर देना, पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार मांगे बिना हो सकता है।

"मुख्य चुनाव" शीर्षक से एक संशोधन अध्यादेश (अब अधिनियम) द्वारा

आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्त) अध्यादेश, 1993। (इसके बाद अध्यादेश के रूप में संदर्भित) "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों (सेवा की शर्त अधिनियम) 1991" में संशोधन करने की मांग की गई थी और तदनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्तों की संख्या

दो तय करें। इसके बाद, खंड 2 अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 324 , भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 1.10.1993 की अधिसूचना द्वारा दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की।

उक्त अध्यादेश की वैधता के साथ-साथ परिणामी

अधिसूचना को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त और एक अन्य ने मनमाना और असंवैधानिक बताया था। सर्वोच्च न्यायालय में यह घोषणा करने के लिए रिट याचिकाएं दायर की गईं कि अध्यादेश मनमाना था, संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इसलिए अमान्य था और रद्द करने के लिए भी था

उक्त अधिसूचना और दो चुनाव आयोग मिशनरियों की नियुक्तियाँ।

याचिकाओं के समर्थन में, यह तर्क दिया गया था कि (ए)। अध्यादेश जारी करने के पीछे की मंशा पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण थी, ताकि इसे दरकिनार किया जा सके।

मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके अधिकार को कम करने के लिए, ताकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल नव नियुक्त चुनाव आयुक्त की सेवाओं का उपयोग करके अनुकूल आदेश प्राप्त कर सके। (ख) संविधान का अनुच्छेद 324, संसद को चुनाव आयोग के कार्य के लेन-देन के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं देता है। इसलिए, सेक। 9 और अध्यादेश के 10 अनुच्छेद 324 में अंतर्निहित योजना के साथ असंगत हैं और इसलिए संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसके अलावा उक्त धाराओं द्वारा निर्धारित प्रावधान मनमाने और अव्यवहारिक हैं, (सी) चुनाव आयुक्तों की संख्या दो निर्धारित करने वाली अधिसूचना मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने याचिकाओं का विरोध किया

वह: (क) अनुच्छेद 324 (2) की भाषा में एक बहु-सदस्य कॉम मिशन की परिकल्पना की गई है और इसलिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी उत्पाद शुल्क लिया जाता है।

उक्त संवैधानिक प्रावधान की योजना के अनुरूप होगा और इसलिए इसे कभी भी दुर्भावनापूर्ण या अधिकार से परे नहीं माना जा सकता है।

संविधान। (ख) चुनाव आयोग को एक बहु-सदस्य निकाय में बदलने के निर्णय का मुख्य चुनाव आयुक्त के कठोर रवैये के कारण केंद्र में सत्तारूढ़ दल की कथित गड़बड़ी से कोई संबंध नहीं था। (ग) एस. एस. धनोआ बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश तैयार किया गया था। भारत संघ और ओआरएस। , [1991] 3 एससीसी 567। (घ) एक बहु-सदस्य निकाय एक सहायक क़ानून के बिना कार्य करने में सक्षम नहीं होता, जिसके लिए प्रावधान किया गया है: अपने व्यवसाय के लेन-देन के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों से निपटना। एक प्रावधान जो अपने सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत के शासन को निर्धारित करता है, इसलिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है और इसे कभी भी मनमाना या संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से परे नहीं बताया जा सकता है।

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, यह न्यायालय पकड़ना: 1.1 . हमारे संविधान निर्माताओं ने यह जिम्मेदारी सौंपी है कि

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना और देश में राजनीतिक और/या निष्पादन संबंधी हस्तक्षेप से अछूते एक स्वतंत्र निकाय के रूप में ऐसे चुनाव कराने का कार्य। यह उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 324 (1) के तहत एक स्थायी निकाय, चुनाव आयोग की स्थापना करके प्राप्त किया जाता है।

कला का खंड (2)। 324 यह प्रावधान है कि उक्त आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की ऐसी संख्या, यदि कोई हो, जो राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करे, शामिल होगी। [119 - ई-जी]

1.2 . बहुतायत की अवधारणा अनुच्छेद 324 के विपरीत व्यापक रूप से लिखी गई है।

खंड (2) जिसमें स्पष्ट रूप से एक बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग की परिकल्पना की गई है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और एक या एक से अधिक चुनाव आयुक्त शामिल हैं। [121 - एच; 122-ए]

एस. एस. धनोआ बनाम भारत संघ और ओआरएस। , [1991] 3 एससीसी 567, संदर्भित

को।

2.1 . ऐसा हो सकता है कि यदि चुनाव आयुक्त एकल सदस्य निकाय है, तो निर्णय मुख्य चुनाव आयोग को लेना पड़ सकता है।

लेकिन फिर भी वे चुनाव आयुक्त के निर्णय होंगे न कि व्यक्ति के। कोई भी निकाय उस संस्था से ऊपर नहीं हो सकता है जिसकी उसे सेवा करनी है। व्यक्ति को संस्थान से अधिक शक्तिशाली के रूप में पेश करना एक गंभीर गलती होगी। इसलिए भले ही चुनाव आयुक्त एक सदस्य निकाय हो, मुख्य चुनाव आयुक्त केवल उस निकाय का एक पदाधिकारी है; इसे अलग तरीके से कहें तो यह आयुक्त का अहंकार है और इससे अधिक नहीं। [129 - बी-डी]

2.2 . यदि चुनाव आयोग एक बहु-सदस्य निकाय है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य है। के कार्य

अतः अध्यक्ष को अपने व्यवसाय के सुचारू लेन-देन के लिए वह सब करना होगा जो आवश्यक है। उसे अपना आचरण इस तरह से करना चाहिए ताकि वह अपने सभी सहयोगियों का विश्वास जीत सके कि आयुक्त उन्हें अपने साथ ले जाए। एक अध्यक्ष को यह हासिल करना मुश्किल हो सकता है यदि वह सोचता है कि अन्य जो आयोग के सदस्य हैं, वे उसके अधीनस्थ हैं। [129 - डी-एच]

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, ब्लैक का कानून शब्दकोश 6 वां संस्करण। पृष्ठ 230, बैलेन्टाइन लॉ डिक्शनरी का तीसरा संस्करण। पृष्ठ 189-190, वेबस्टर का नया 20 वां

सेंचुरी डिक्शनरी, बिना संक्षिप्त, दूसरा संस्करण। पृष्ठ 299 और अय्यर का न्यायिक शब्दकोश 11 वां संस्करण। पृष्ठ 238-'अध्यक्ष' के अर्थ के लिए संदर्भित।

3. चुनाव आयुक्त एक सार्वजनिक कार्य करता है। चुनाव आयोग के कार्य अनिवार्य रूप से प्रशासनिक हैं लेकिन

कुछ न्यायिक और विधायी कार्य भी। प्रशासनिक कार्यों के अलावा इसे अर्ध न्यायिक कर्तव्यों और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1995] का पालन करने के लिए भी बुलाया जा सकता है।

अधीनस्थ विधान निर्माण कार्य करना। चुनाव आयुक्त क्षेत्रीय मिशनरियों के विपरीत चुनाव आयोग का एक हिस्सा होते हैं, और इसलिए निर्णय लेने में उनकी भूमिका होती है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त को इस अर्थ में श्रेष्ठ माना जाता है कि उनका शब्द अंतिम है, तो वह अन्य चुनाव आयुक्तों को गैर-कार्यात्मक या सजावटी बना देगा। इस तरह के इरादे को कला से बाहर निकालना मुश्किल है। 324 इसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं को जाता है। [129 - एच; 130-सी-ई]

एम. एस. गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, [1978] 2 एससीआर 272, संदर्भित

को।

4.1 . प्रमुख की स्थिति के बीच अंतर करने वाली विशेषता

निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, जैसा कि अनुच्छेद में परिकल्पित है। 324 यह अनिवार्य रूप से उनके कार्यकाल के कारण है। [130 - ई, एफ]

सायनर को उसकी नियुक्ति के बाद उसके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता है। इस तरह की सुरक्षा चुनाव आयुक्तों को नहीं दी जाती है। वह यह है कि संभवत: इसलिए कि चुनाव आयुक्त के पद अस्थायी हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, तो अकेले यह विशेषता इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है कि सभी मामलों में अंतिम शब्द मुख्य चुनाव के पास है

कमिश्नर। [126 - ई-एफ]

4.3 . दूसरा आधार हटाने योग्य से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में उन्हें इसी तरह पद से हटाया जा सकता है और

समान आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जबकि चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। हालाँकि, यह मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्च दर्जा देने का संकेत नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त का उद्देश्य स्थायी रूप से कार्य करना है और इसलिए उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित और संरक्षित करने के लिए, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाना था। मुख्य चुनाव आयुक्त के बिना चुनाव आयोग नहीं हो सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों के मामले में ऐसा नहीं है। चीजों की प्रकृति में। चुनाव आयुक्तों को उस प्रकार की अपरिवर्तनीयता प्रदान नहीं की जा सकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त को दी जाती है। अगर ऐसा करना था, तो कला की पूरी योजना। 324 एक बदलाव से गुजरना होगा। लेकिन यह तथ्य कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्थायी पदधारी हैं, उन्हें उच्चतर पद प्रदान नहीं कर सकता है।

चुनाव आयुक्त से अधिक का दर्जा। [126 - एफ-एच; 127-ए, बी] T.N.SESHAN वी।

यू. ओ. आई.

111

5. न तो अनुच्छेद 324 और न ही संविधान में कोई अन्य प्रावधान

यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कैसे एक बहु-सदस्य चुनाव आयुक्त अपना कार्य करेगा और न ही इस संबंध में कोई परंपरा विकसित हुई है। यही कारण है कि अतीत के कड़वे अनुभव को ध्यान में रखते हुए, जिसका धनोआ के मामले में एक संदर्भ दिया गया है, इस न्यायालय ने सोचा कि इस अंतर को एक उचित वैधानिक प्रावधान द्वारा भरा जा सकता है, जिससे इस संबंध में विधायी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। उक्त निर्णय से एक संकेत लेते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया जिसके तहत एक नया अध्याय जिसमें अनु. 9 और 10 को अधिनियम में जोड़ा गया था, जो दर्शाता है कि चुनाव आयोग अपना कार्य कैसे करेगा। यद्यपि उक्त प्रावधानों ने इस उम्मीद को प्रकट किया है कि आयोग एक स्वर में निर्णय लेने में सक्षम होगा, लेकिन यदि यह उम्मीद बनी रहती है, तो नियम बहुमत को लागू करना चाहिए। धारा 10 स्पष्ट रूप से सर्वसम्मति का प्रावधान करती है। भले ही यह माना जाए कि अकेले आयोग यह निर्धारित करने में सक्षम था कि यह कैसे

अपने व्यवसाय का लेन-देन करेगा, उसे उसी पैटर्न का पालन करना होगा जैसा कि सेक में बताया गया है। 10. [131 - ए-बी, एफ]

6. हालांकि मुख्य चुनाव की कुछ सेवा शर्तें

आयुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वैध रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होने का दावा नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति का रखरखाव राष्ट्रीय हित में अत्यधिक वांछनीय है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए दावा समीकरण के लिए अन्य से संबंधित कार्मिक केवल इसलिए कि उन न्यायालयों द्वारा पहले प्रयोग की जाने वाली कुछ अधिकारिता उन्हें हस्तांतरित की जाती है, संवैधानिक और वैधानिक अधिकारियों के बीच अंतर को महसूस नहीं करते हैं। इसलिए, यदि इससे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति प्रभावित होने की संभावना है, तो सरकार को पहले मुख्य न्यायाधीश का विचार लिए बिना, वरीयता के वारंट में समानता प्रदान नहीं करनी चाहिए या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

भारत से। [139 - ए, बी, एफ-एच; 140-ए]

7. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तर्क

यह कि अप्रकाशित प्रावधान संविधान के साथ धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि वे चुनाव आयोग के होने के उद्देश्य को विफल करने के लिए बनाए गए और गणना किए गए हैं, सवाल पूछना है। [132 - ई, एफ]

अनुच्छेद 324 के खंड (2) और (5) दोनों में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों के लिए एक क़ानून का विचार किया गया है।

वाइस। विवादित कानून इन दोनों मामलों और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1995] एस. यू. पी. पी. के प्रावधानों के लिए प्रावधान करता है।

112

उस प्रभाव को असंवैधानिक के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि वे कला के खंड (2) और (5) द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए हैं। 324. एक बार जब बहु-सदस्य आयोग के गठन का प्रावधान अनुपलब्ध हो जाता है,

आनुषंगिक प्रावधानों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। [138 - डी]

8. आक्षेपित अध्यादेश, अधिसूचना और परिणामी या

आदेश और नियुक्तियों को उनकी संपूर्णता में बरकरार रखा जाता है। [140 - एफ]

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: की लिखित याचिका (सी) संख्या 805

1993 आदि। आदि।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

एम. के. बनर्जी, भारत के महान्यायवादी, M.Chandra शेखर, एड

डायशनल सॉलिसिटर जनरल, जी. रामास्वामी, एन. ए. पालखीवाला, राम जेठ

मलानी, ओ. पी. शर्मा पी. पी. राव, सोली जे. सोराबजी, के. के. वेणुगोपाल, के.

परासरन, ए. के. गांगुली, जी. राजगोपाल, एस. मुरलीधर, संजय हेगड़े, एन. एल. गणपति, एस. वालिया, मोहित माथुर, एच. देवराजन, निरंजन रेड्डी,

825/93 , एम. एम. कश्यप, एन. एन. गुप्टू, एच. के. पुरी, ए. वी. रंगम, A.Ran गणधन, सुमंत भारद्वाज, ए. एस. भासमे, एस. के. निंगोम्बन, सुनील दोरगा,

ई. आर. कुमार, गोपाल जैन, डब्ल्यू. सी. चोपड़ा, पंकज चोपड़ा, अमरियारपुथम, अरुणा माथुर, पी. आर. सीतारमन, सुश्री नीता अग्रवाल, एन. जनार्दनन,

के. आर. नागराजा, ई. सी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल, अतुल शर्मा, पूर्णिमा

उत्तरदाता के लिए भट काक, ए. वी. पल्ली, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, (व्यक्तिगत रूप से) सी. ए. सं. 504/94 में , मुकुल मुद्गल, सुश्री इंदु मल्होत्रा, सुश्री शिरीन

खजुरिया, के. वी. विश्वनाथन, सुश्री ए. सुभाषिनी, पी. परमेश्वरन, सुशील प्रकाश, ए. सुब्बाराव, नवीन प्रकाश और आर. बी. मिश्रा

पार्टियाँ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एच. एम. डी., सी. जे. भारत के राष्ट्रपति, शक्तियों का प्रयोग करते हुए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा उन पर आरोपित किया गया,

"मुख्य चुनाव" शीर्षक से एक अध्यादेश (1993 का सं. 32) जारी किया।

आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्त) संशोधन अध्यादेश, 1993 (जिसे इसके बाद 'अध्यादेश' कहा जाता है)

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को संशोधित करें

(सेवा की शर्त) अधिनियम, 1991 "(इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाता है)। यह या दिनान्स 1 अक्टूबर, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

हम 1991 के अधिनियम में किए गए संशोधनों को देखते हैं, उक्त अध्यादेश द्वारा 1991 के अधिनियम के प्रावधानों को नोटिस करना उचित हो सकता है। जैसा कि अधिनियम के लंबे शीर्षक से पता चलता है कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त (इसके बाद 'सीईसी' कहा जाता है) और चुनाव आयोग की सेवा की शर्तों को निर्धारित करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत नियुक्त मिशनरी (जिन्हें इसके बाद 'ईसी' कहा जाता है)। धारा 3 (1) में प्रावधान है कि सी. ई. सी. को एक वेतन दिया जाएगा जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर है। धारा 3 (2) में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को एक वेतन दिया जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर है। धारा 4 सी. ई. सी. और ई. सी. के पद का कार्यकाल उस तारीख से छह साल निर्धारित करती है जिस दिन पदधारी अपने पद का कार्यभार संभालता है, बशर्ते कि पदधारी अपना पद खाली कर दे।

सी. ई. सी. के मामले में उनकी आयु 65 वर्ष और निर्वाचन आयोग की आयु 62 वर्ष होने पर, इस तथ्य के बावजूद कि पद का कार्यकाल छह वर्ष की अवधि के लिए है। धारा 8 यात्रा भत्ता, किराया मुक्त निवास, आय के भुगतान से छूट-ऐसे किराया मुक्त निवास के वाल्व पर कर, परिवहन सुविधा, कुल अनुदान, चिकित्सा सुविधाओं आदि का लाभ प्रदान करती है, जो क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सी. ई. सी. और ई. सी. पर लागू होता है। अध्यादेश द्वारा अधिनियम के शीर्षक को "और चुनाव आयोग द्वारा कार्य के लेन-देन की प्रक्रिया और" शब्दों के लिए "और मामलों के लिए" शब्दों को प्रतिस्थापित करके संशोधित करने की मांग की गई थी। इन शब्दों के प्रतिस्थापन से अधिनियम का लंबा शीर्षक, सी. ई. सी. और अन्य निर्वाचन आयोगों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने और चुनाव आयोग द्वारा कार्य के लेन-देन की प्रक्रिया और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम के रूप में और लंबा हो गया। "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त मिशनरियों (सेवा की शर्त)" शब्दों और कोष्ठकों के लिए मूल अधिनियम की धारा 1 में "चुनाव आयोग की सेवा की शर्तें और कार्य के हस्तांतरण)" शब्द और कोष्ठक इस परिणाम के साथ प्रतिस्थापित किए गए कि संशोधित प्रावधान को चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्त और कार्य का लेनदेन) अधिनियम, 1991 के रूप में पढ़ा गया। धारा 2 में परिभाषा खंड में भी परिवर्तन हुआ, जिसमें, विद्यमान,

खंड (बी) को खंड (सी) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया और एक नया खंड (बी) प्रतिस्थापित किया गया जिसके द्वारा "चुनाव आयोग" अभिव्यक्ति आई

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट चुनाव आयोग के रूप में परिभाषित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप अन्य स्थानों पर भी परिवर्तन किए गए। धारा 3 की उप-धारा (1) में, "मुख्य चुनाव आयुक्त" शब्दों के बाद, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1995] एस. यू. पी.

114

"और अन्य चुनाव आयुक्त" शब्द इस परिणाम के साथ जोड़े गए कि उन्हें देय वेतन के संबंध में समान स्थान दिया गया और उप-धारा (2) को हटा दिया गया। धारा 4 में पहला परंतुक निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया:

" बशर्ते कि जहां मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त समाप्ति से पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं।

छह साल की उक्त अवधि में से, वह उस तारीख को अपना पद खाली कर देगा।

जिस पर वह उक्त आयु प्राप्त करता है।

इस प्रकार सीईसी और ईसी दोनों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तय की गई थी। यदि वे छह वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें परंतुक को देखते हुए पद खाली करना होगा।

65 वर्ष की आयु प्राप्त करना। धारा 6, उप-धारा (2) में, "मुख्य चुनाव आयुक्त" शब्दों के बाद "या एक चुनाव आयुक्त" शब्द हैं। अंत:स्थापित किया गया और "उप-धारा (4)" शब्दों के स्थान पर "उप-धारा (3)" शब्द रखे गए। इसमें आगे हटाने का प्रावधान किया गया था

उप-धारा (3) और उप-धारा (4) को उप-धारा (3) के रूप में पुन: क्रमांकित करने के लिए और बशर्ते कि खंड (बी) में "या, जैसा भी मामला हो, 62 वर्ष" शब्दों को हटा दिया जाएगा। प्रधान अधिनियम की धारा 8 के बाद, अध्यादेश द्वारा एक नया

अध्याय जोड़ा गया जिसमें दो प्रावधान थे, अर्थात् धारा 9 और 10। इस प्रकार जोड़ा गया नया अध्याय हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है और इस स्तर पर पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:

" अध्याय III

चुनाव आयोग के व्यवसाय का हस्तांतरण एसआईओएन

9. निर्वाचन आयोग का कार्य इस प्रकार किया जाएगा -

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

(10) (1) निर्वाचन आयोग सर्वसम्मत निर्णय द्वारा,

व्यवसाय के लेन-देन की प्रक्रिया को भी विनियमित करना और मुख्य चुनाव आयोगों के बीच कार्य का आवंटन

सायनर और अन्य चुनाव आयुक्त।

(2) उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, चुनाव आयोग के सभी कार्यों का जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से संचालन किया जाएगा।

(3) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि मुख्य चुनाव

आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की राय अलग है।

किसी भी मामले पर, ऐसे मामले का निर्णय इसके अनुसार किया जाएगा - बहुमत की राय "।

अध्यादेश के प्रकाशन के दिन, 1 अक्टूबर, 1993 को,

भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अगले आदेश तक, चुनाव आयुक्तों (सीईसी के अलावा) की संख्या दो निर्धारित की। राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर, 1993 से श्री एम. एस. गिल और श्री जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया।

पहला साल्वो चो द्वारा दागा गया था। S.Ramaswamy, एक पत्रकार, 13 तारीख को

अक्टूबर, 1993। 1993 की एक रिट याचिका (सिविल) संख्या 791 द्वारा उन्होंने एक घोषणा के लिए अनुरोध किया कि अध्यादेश मनमाना, असंवैधानिक और अमान्य था और श्री एम. एस. गिल और श्री जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति की दो नियुक्तियों पर चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करने वाली अधिसूचनाओं को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया। इसके बाद 1993 की रिट याचिका संख्या 805 को मौजूदा सी. ई. सी. ने खुद 26 अक्टूबर, 1993 को इसी तरह की राहत का दावा किया था। अध्यादेश और अधिसूचनाओं की वैधता पर सवाल उठाते हुए दो अन्य रिट याचिकाएं भी दायर की गईं।

अंतरिम रोक के साथ-साथ पेश करने के लिए आवेदन पर सी. ई. सी. द्वारा दायर रिट याचिका में उन सभी में नियम जारी करने का निर्देश दस्तावेजों को जारी करने का आदेश दिया गया और निम्नलिखित प्रभाव के लिए एक विज्ञापन-अंतरिम आदेश पारित किया गया:

" अगले आदेश तक, आयोग के सुचारू और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए और प्रशासन के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया दोनों में भ्रम से बचने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग के काम के पूर्ण नियंत्रण में रहेंगे। वह दूसरों के विचारों का पता लगा सकता है।

समय-समय पर आयोग के समक्ष आने वाले मुद्दों पर आयुक्त या उनमें से जो वह चुनता है। हालांकि,

वह उनके विचारों से बंधा नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग के कर्मचारियों के साथ-साथ बाहरी एजेंसियों को निर्देश जारी करने का हकदार होगा और कोई अन्य आयुक्त इस तरह के निर्देश जारी नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1995] एस. यू. पी.

116 भारत संघ के विद्वान महान्यायवादी और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के विद्वान महान्यायवादी को सुनने के बाद, दिनांक 1 के एक बाद के आदेश द्वारा, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी राज्य सरकारें जो सुनना चाहती हैं, उन्हें उनके वकील के माध्यम से सुना जाएगा और आगे निर्देश दिया कि अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। अंत में, इसने कहा कि चूंकि विशेष रूप से अनुच्छेद 324 की व्याख्या से संबंधित प्रश्न शामिल हैं, इसलिए मामलों को संविधान पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

उपरोक्त रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, अध्यादेश

बिना किसी परिवर्तन के 4 जनवरी, 1994 को एक अधिनियम (1994 का अधिनियम संख्या 4) बन गया।

इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अनुच्छेद 324 पर ध्यान देना उचित होगा।

संविधान से। यह नीचे लिखा है:

" 324. निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना। -- (1) प्रत्येक राज्य की संसद और विधान सभा के लिए और इस संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में चुनाव आयोग मिशन के रूप में संदर्भित किया गया है)।

(2) चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और इतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी।

आयुक्त, संसद द्वारा उस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाएंगे।

(3) जब कोई अन्य चुनाव आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। चुनाव आयोग।

(4) लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले, और पहले आम चुनाव से पहले और उसके बाद ऐसी परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव से पहले, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श के बाद भी नियुक्ति कर सकता है।

कार्यों के निष्पादन में चुनाव आयोग की सहायता करना। आयोग को खंड (1) द्वारा प्रदत्त।

(5) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन,

चुनाव आयोग की सेवा की शर्तें और कार्यकाल सायनर और क्षेत्रीय आयुक्त इस तरह के होंगे -

राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित कर सकते हैं:

बशर्ते कि मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होगा समान तरीके से और इसी तरह के अलावा अपने कार्यालय से हटा दिया गया

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आधार और की शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा में भिन्नता नहीं होगी -

उनकी नियुक्ति के बाद उनका नुकसान:

बशर्ते कि कोई अन्य चुनाव आयुक्त या

क्षेत्रीय आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाएगा सिवाय इसके कि

मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर।

(6) राष्ट्रपति या किसी राज्य की सरकार, जब ऐसा होगा,

चुनाव आयोग द्वारा अनुरोध किया गया, उपलब्ध कराएँ

निर्वाचन आयोग या किसी क्षेत्रीय आयुक्त के लिए जैसे कर्मचारी

प्रदत्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकता है

निर्वाचन आयोग खंड (1) द्वारा "।

संक्षिप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिस पर की संवैधानिक वैधता

उपरोक्त याचिकाओं में अध्यादेश (अब अधिनियम) और निर्वाचन आयोगों के परिणामी आदेशों और नियुक्तियों पर व्यापक रूप से सवाल उठाए गए हैं इस स्तर पर निम्नानुसार संकेत दिया गया है:

वर्तमान सीईसी का दावा है कि उनकी नियुक्ति के बाद 12.12.1990 पर

सभी ने आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन पर जोर दिया

चुनाव के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और पुलिस बल को तैनात करने में सरकार की विफलता और सत्तारूढ़ दल त्रिपुरा में चुनाव हार गया क्योंकि सीईसी द्वारा गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप चुनाव स्थगित कर दिया गया था चुनावों के बारे में। सत्तारूढ़ दल ने सी. ई. सी. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1995] एस. यू. पी. को प्रभावित करने का प्रयास किया।

झोपड़ी ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने पार्टी के दूतों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी थी। सीईसी ने इसे लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की। कर्मचारी और बल के लिए चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार। सीईसी ने सत्तारूढ़ दल के अनुरोध के बावजूद चार राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव स्थगित करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री सहित सत्तारूढ़ दल सी. ई. सी. के इस तरह के अटूट रवैये से नाराज हो गया। इसलिए सत्तारूढ़ दल सी. ई. सी. की शक्तियों को निलंबित करने और उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए है।

उन्होंने कानून में संशोधन करने का फैसला किया और संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत राष्ट्रपति की शक्ति का दुरुपयोग करते हुए 1 अक्टूबर, 1993 को अधिसूचना जारी कर चुनाव आयोगों की संख्या दो निर्धारित की और साथ ही श्री एम. एस. गिल और श्री जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति को अन्य दो चुनाव आयोगों के रूप में नियुक्त किया। सी. ई. सी. न केवल उपरोक्त अधिसूचनाओं और नियुक्तियों को जारी करने के लिए दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाता है, बल्कि यह भी आरोप लगाता है कि इसके पीछे की मंशा

अध्यादेश जारी करना सी. ई. सी. को दरकिनार करना और उनके अधिकार को कम करना था ताकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल नव नियुक्त निर्वाचन आयोगों की सेवाओं का उपयोग करके अनुकूल आदेश प्राप्त कर सके।

अध्यादेश (अब अधिनियम) की धारा 9 और 10 को अतिवादी के रूप में चुनौती दी गई है

संविधान को इस दलील पर अधिकार है कि वे संविधान के अनुच्छेद 324 में अंतर्निहित योजना के साथ असंगत हैं, जिसमें उक्त अनुच्छेद 324 ने संसद को चुनाव आयोग के कार्य के लेन-देन के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं दी थी। धारा 10 को भी चुनौती दी गई है

यह आधार है कि यह मनमाना और अव्यवहारिक है। इसलिए अन्य निर्वाचन आयोगों की संख्या दो तय करने की अधिसूचना को भी मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई है।

रिट याचिकाओं का प्रतिवाद प्रत्यर्थियों द्वारा किया जाता है। , भारत संघ और दो अन्य ईसी। श्री एम. एस. गिल और श्री जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति

पूरी तरह से गलत धारणा। संघ सरकार की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि विभिन्न सलाहकार निकायों ने समय-समय पर एक बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग की मांग की थी। यह इस आरोप का खंडन करता है कि चुनाव आयोग को एक बहु-सदस्य निकाय में बदलने के निर्णय का सीईसी के कठोर रवैये के कारण केंद्र में सत्तारूढ़ दल की कथित गड़बड़ी से कोई संबंध था। यह आगे कहा गया है कि बहु-सदस्य निकाय व्यवसाय के लेन-देन के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए एक सहायक क़ानून के बिना कार्य करने में सक्षम नहीं होता। अध्यादेश T.N.SESHAN v तैयार किया गया था।

एस. एस. धनोआ बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए। यू. ओ. आई. और अन्य। , [1991] 3 एससीसी 567। इस बात से दृढ़ता से इनकार किया जाता है कि कानून में परिवर्तनों को दुर्भावनापूर्ण बनाया गया था ताकि सी. ई. सी. को प्रस्तुत किया जा सके या उनके अधिकार को कम किया जा सके, यह प्रावधान करके कि, मतभेद की स्थिति में, बहुमत का विचार प्रबल होगा। यह है।

उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 324 (2) की सरल भाषा में एक बहु-सदस्यीय आयोग की परिकल्पना की गई है और इसलिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गई कोई भी कवायद उक्त संवैधानिक प्रावधान की योजना के अनुरूप होगी और इसलिए, इसे कभी भी दुर्भावनापूर्ण या संविधान के विपरीत नहीं माना जा सकता है। इस आशय का प्रावधान कि चुनाव आयोग के तीन सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में, बहुमत का दृष्टिकोण प्रबल होना चाहिए, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है और इसे कभी भी मनमाना या संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, भारत संघ ने तर्क दिया है कि रिट याचिकाएं पूरी तरह से गलत हैं और लागत के साथ खारिज किए जाने के योग्य हैं।

हमारे संविधान की प्रस्तावना घोषणा करती है कि हम एक हैं

लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र संवैधानिक राष्ट्रीय व्यवस्था की मूल विशेषता होने के कारण, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि हमारे विधायी निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र के विकास की गारंटी देंगे। चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र निकाय को सौंपी जानी चाहिए जो राजनीतिक और/या कार्यकारी हस्तक्षेप से अछूता हो। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अंतर्निहित है कि जिस एजेंसी को विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने का काम सौंपा गया है, उसे पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए ताकि वह एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य कर सके। सत्ता में पार्टी या उस समय की कार्यपालिका से बाहरी दबाव। यह उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 324 (1) के तहत एक स्थायी निकाय, चुनाव आयोग की स्थापना द्वारा प्राप्त किया जाता है। देश में पूरी चुनाव प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण उक्त खंड के तहत चुनाव आयोग नामक एक आयोग में निहित किया गया है। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में चुनाव आयोग के गठन के लिए यह प्रावधान किया गया है कि इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इतनी संख्या में निर्वाचन आयोग, यदि कोई हों, शामिल होंगे जो राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करें। इस प्रकार इस खंड की सरल भाषा से यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग सीईसी और जब उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो ईसी से बना होता है। सी. ई. सी. के कार्यालय की परिकल्पना एक स्थायी स्थिरता के रूप में की गई है, लेकिन यह ई. सी. के लिए नहीं कहा जा सकता है जैसा कि सुपर कोर्ट रिपोर्ट [1995] एस. यू. पी. पी. के उपयोग से प्रकट किया गया है।

120

"यदि कोई हो" शब्दों से। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में बहस के दौरान इस खंड के उद्देश्य को समझाते हुए कहा:

" उपखंड (2) में कहा गया है कि एक मुख्य चुनाव आयोग होगा।

समय-समय पर नियुक्त कर सकते हैं। प्रारूपण समिति के समक्ष दो विकल्प थे, अर्थात्, या तो एक स्थायी निकाय होना, जिसमें चुनाव आयोग के चार या पांच सदस्य शामिल हों। बिना किसी विराम के पूरे समय कार्यालय में बने रहेंगे, या

राष्ट्रपति को उस समय एक तदर्थ निकाय नियुक्त करने की अनुमति दें जब चुनाव होता है। समिति ने एक मध्यम मार्ग का नेतृत्व किया है। उप-मसौदा समिति ने क्या प्रस्तावित किया

खंड (2) में एक व्यक्ति को स्थायी रूप से पद पर रखा जाना है जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, ताकि कंकाल तंत्र हमेशा उपलब्ध रहें।

उक्त खंड (2) की सरल भाषा से यह स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक स्वतंत्र निकाय या आयोग की स्थापना की आवश्यकता को महसूस किया जो स्थायी रूप से कम से कम एक अधिकारी, अर्थात् सीईसी के साथ सत्र में होगा, और इसे राष्ट्रपति पर छोड़ दिया कि वह आयोग में इतनी संख्या में ईसी जोड़ें जो वह समय-समय पर उचित समझे। उक्त अनुच्छेद के खंड (3) में यह स्पष्ट किया गया है कि जब चुनाव आयोग एक बहु-सदस्य निकाय होगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका क्या होगी, यह उक्त लेख में विशेष रूप से नहीं बताया गया है और हम इस प्रश्न पर आगे चर्चा करेंगे। उक्त अनुच्छेद के खंड (4) में खंड (1) में निर्धारित कार्यों के निष्पादन में चुनाव आयोग की सहायता के लिए आर. सी. की नियुक्ति का भी प्रावधान है। जहां तक चुनाव आयोग के गठन का संबंध है, यह संक्षेप में अनुच्छेद 324 की योजना है।

अब हम संक्षेप में प्रत्येक पदाधिकारी की स्थिति पर ध्यान दे सकते हैं

चुनाव आयोग। सबसे पहले, खंड (2) में कहा गया है कि सी. ई. सी. और अन्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति, संसद द्वारा उस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अतः राष्ट्रपति नियुक्ति का प्राधिकारी होगा। खंड (5) में प्रावधान है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, निर्वाचन आयोगों और आर. सी. की सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल ऐसा होगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम द्वारा निर्धारित किया जाए। बेशक आर. सी. चुनाव आयोग मिशन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि केवल आयोग की मदद करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात, सी. ई. सी. और ई. सी., यदि कोई हो। जैसा कि हमने पहले कार्यकाल का उल्लेख किया है, T.N.SESHAN v।

यू. ओ. एल. [ए. एच. एम. ए. डी., जे.]

121

सी. ई. सी. और ई. सी. के वेतन, भत्ते और अन्य अनुलाभ इस अधिनियम के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष निर्धारित किए गए थे। अध्यादेश के बाद इसमें बदलाव आया है जिसने अधिनियम में इस तरह से संशोधन किया है ताकि उन्हें समान रूप से रखा जा सके। हालांकि,

अनुच्छेद 324 के खंड (4) के परंतुक में कहा गया है कि (i) सी. ई. सी. को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों के अलावा अपने पद से नहीं हटाया जाएगा और (ii) सी. ई. सी. की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा। संसद की शक्ति पर इन दो सीमाओं का उद्देश्य राजनीतिक और/या कार्यकारी हस्तक्षेप से सीईसी की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। निर्वाचन आयोगों के साथ-साथ आर. सी. के मामले में, खंड (5) के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि उन्हें सी. ई. सी. की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि खंड (4) के तहत, आरसी की नियुक्ति से पहले, चुनाव आयोग (सीईसी नहीं) के साथ परामर्श किया जाता है

आवश्यक है कि निर्वाचन आयोगों की नियुक्तियों के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ई. सी. और आर. सी. द्वारा एक बार नियुक्त किए जाने का प्रावधान नहीं हो सकता है

उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटा दिया गया सिवाय इसके कि

सीईसी की सिफारिश उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। इस संबंध में अनुच्छेद 324 की योजना यह है कि खंड (5) के पहले परंतुक द्वारा सी. ई. सी. का अपमान करने के बाद, निर्वाचन आयोगों और आर. सी. को यह प्रावधान करके काम करने की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है कि उन्हें सी. ई. सी. की सिफारिश के अलावा हटाया नहीं जा सकता है। बेशक, हटाने की सिफारिश समझदारी और संज्ञानात्मक विचारों पर आधारित होनी चाहिए जो चुनाव आयोग के कुशल कामकाज से संबंधित होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विशेषाधिकार सीईसी को यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है कि ईसी के साथ-साथ आरसी भी उस समय के राजनीतिक या कार्यकारी आकाओं की दया पर निर्भर न हों। यह महसूस करना आवश्यक है कि हटाने की कार्यपालिका की शक्ति पर यह नियंत्रण खंड (5) के दूसरे परंतुक में न केवल इन अधिकारियों बल्कि एक निकाय के रूप में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाया गया है। यदि, इसलिए, सी. ई. सी. द्वारा अपनी सनक और इच्छा के अनुसार शक्ति का प्रयोग किया जाना था, तो सी. ई. सी. स्वयं उत्पीड़न का साधन बन जाएगा और यदि उन्हें सी. ई. सी. द्वारा उन्हें हटाने की सिफारिश करने की धमकी के तहत काम करने की आवश्यकता होती है, तो वह ई. सी. और आर. सी. की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा। इसलिए इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि सी. ई. सी. को इस शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए जब चुनाव आयोग के कुशल कामकाज के लिए अनुकूल वैध कारण मौजूद हों। यह, संक्षेप में कहा गया है, चुनाव आयोग का गठन करने वाले विभिन्न अधिकारियों की स्थिति का संकेत देता है। बहुतायत की अवधारणा अनुच्छेद 324, खंड (2) के

सामने व्यापक रूप से लिखी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से एक बहु-सदस्य चुनाव आयोग की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1995] एस. यू. पी. की परिकल्पना की गई है।

122

सीईसी और एक या अधिक ईसी को सम्मानित करना। ऐसी स्थिति को देखते हुए, खंड (3) में प्रावधान है कि एक बहु-सदस्य निकाय के मामले में सी. ई. सी. इसका अध्यक्ष होगा। यदि एक बहु-सदस्य चुनाव आयोग पर विचार नहीं किया गया था, तो खंड (3) में सीईसी को इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता कहां थी? इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चुनाव आयोग एक बहु-सदस्य निकाय हो सकता है। यदि अनुच्छेद 324 ए पर विचार करता है

बहु-सदस्य निकाय, अन्य दो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली विवादित अधिसूचनाओं को केवल उसी आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता है। हम यहाँ एस. एस. धनोआ बनाम मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ की टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ उद्धृत कर सकते हैं। भारत संघ और अन्य, [1991] 3 एस. सी. सी. 567, अनुच्छेद 26 के अनुसार:

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि दो सिर एक से बेहतर हैं, और

विशेष रूप से जब चुनाव आयोग जैसी संस्था है

महत्वपूर्ण कार्यों को सौंपा गया है, और उन्हें निष्पादित करने के लिए अनन्य अनियंत्रित शक्तियों से लैस है, यह दोनों आवश्यक और वांछनीय है कि शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, हालांकि, वह सर्वज्ञानी हो सकता है। यह लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। यह सच है कि किसी संस्थान की स्वतंत्रता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो इसे संचालित करते हैं, न कि उनकी संख्या पर। एक एकल व्यक्ति कभी-कभी सभी खिंचावों और दबावों का सामना करने में सक्षम साबित हो सकता है, जो कई लोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि, जब विशाल

शक्तियों का प्रयोग एक संस्था द्वारा किया जाता है जो इसके लिए उत्तरदायी है - नहीं, अपने मामलों को एक से अधिक हाथों में सौंपना राजनीतिक है। यह विवेक और मनमानेपन की कमी को सुनिश्चित करने में मदद करता है। हालांकि, तथ्य यह है कि जहां एक से अधिक व्यक्ति एक संस्थान का संचालन करते हैं, उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, यदि

संस्थान को शून्य नहीं होना चाहिए "।

यह महसूस किया जाना चाहिए कि ये टिप्पणियां इस तथ्य के बावजूद की गई थीं कि विद्वान न्यायाधीश जीवित थे और उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के दो पद बनाने और याचिकाकर्ता धनोआ की नियुक्ति करने वाली अधिसूचनाओं को रद्द करने की आवश्यकता थी।

उनके लिए एक और।

इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है और वास्तव में ऐसा कभी नहीं था कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। अनुच्छेद 324 की योजना से यह भी स्पष्ट है कि उक्त निकाय के पास

स्थायी पदधारी के रूप में सी. ई. सी. होगा और खंड (2) के तहत ऐसी संख्या में अन्य ई. सी. होंगे, यदि

यू. ओ. आई. [अहमदिया, जे.]

123

राष्ट्रपति के रूप में कोई भी व्यक्ति नियुक्त करना उचित समझ सकता है। की योजना

इसलिए अनुच्छेद 324 यह है कि एक स्थायी निकाय होगा जिसे चुनाव आयोग कहा जाएगा और एक स्थायी पदाधिकारी को चुनाव आयोग कहा जाएगा।

सीईसी। यदि राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझते हैं तो चुनाव आयोग इसलिए एकल सदस्य निकाय या बहु-सदस्य निकाय हो सकता है। एक या अधिक ईसी। इस बिंदु तक कोई कठिनाई नहीं है। यह तर्क कि एक बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग काम नहीं करेगा और इसलिए उसकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमारा संविधान

राष्ट्र-निर्माताओं ने एक बहु-सदस्य निकाय का प्रावधान किया है। उन्होंने इस तरह के निकाय के लिए प्रदान करने की आवश्यकता देखी। यदि यह निवेदन स्वीकार किया जाता है कि एक बहु-सदस्य निकाय अव्यवहारिक होगा तो यह संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) और (3) को नष्ट करने या रद्द करने के समान होगा। हालाँकि, तर्क को मजबूत करने के लिए धनोआ के मामले पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी। उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों के बिल्कुल विपरीत थे। उस मामले में राष्ट्रपति खंड (2) के अनुसरण में जारी अधिसूचना द्वारा

अनुच्छेद 324 ने याचिकाकर्ता और एक दूसरे को निर्वाचन आयोग के रूप में नियुक्त एक अलग अधिसूचना द्वारा सीईसी के अलावा निर्वाचन आयोगों की संख्या दो और कुछ दिनों के लिए निर्धारित की। अनुच्छेद 324 के खंड (5) के तहत जारी एक और अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ने उनके कार्यकाल और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाए। लगभग कुछ महीनों तक बहु-सदस्य निकाय के कामकाज को देखने के बाद, राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से दो अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसमें अधिसूचना जिसके द्वारा निर्वाचन आयोग के दो पद बनाए गए थे और अधिसूचना जिसके द्वारा याचिकाकर्ता और एक

इसके लिए एक और व्यक्ति को नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता एस. एस. धनोआ ने पहले की अधिसूचनाओं को रद्द करने वाली अधिसूचनाओं को इस आधार पर चुनौती दी कि एक बार चुनाव आयोग की नियुक्ति के बाद वह निर्धारित पूर्ण कार्यकाल के लिए पद पर बना रहता है -

अनुच्छेद 324 के खंड (5) के तहत बनाए गए नियम और, किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता

सी. ई. सी. की सिफारिश के अलावा इसे हटाया नहीं जा सका। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता और उसके सहयोगी से छुटकारा पाने के लिए सी. ई. सी. की सलाह के तहत अधिसूचनाएं दुर्भावनापूर्ण रूप से जारी की गईं क्योंकि सी. ई. सी. शुरू से ही निर्वाचन आयोगों के पदों के निर्माण के प्रति असंवेदनशील या विरोधी था। याचिकाकर्ता के अनुसार,

एक ओर सी. ई. सी. और दूसरी ओर ई. सी. के बीच मतभेद और चूंकि सी. ई. सी. चाहते थे कि उनके पास एकमात्र शक्ति होनी चाहिए यह तय करने के लिए कि उन्हें चुनाव आयोगों का संगठन पसंद नहीं था।

इस न्यायालय की खंड पीठ से यह निर्णय लेने के लिए जो प्रमुख प्रश्न पूछा गया था, वह यह था कि क्या राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के दो पदों और बाद में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1995] उप का सृजन करने वाली पिछली अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था।

124

याचिकाकर्ता और उसके सहयोगी की ई. सी. के रूप में नियुक्ति। न्यायालय ने एक तथ्य के रूप में पाया कि निर्वाचन आयोग के दो पदों को बनाने और याचिकाकर्ता और उसके सहयोगी को नियुक्त करके उन्हें भरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त काम को दो निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति के बजाय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर संभाला जा सकता था। इसलिए न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि स्थापना के समय से ही सरकार ने निर्वाचन आयोग के दो पदों को बनाने और उन्हें भरने में त्रुटि की है। हम वर्तमान में इस सवाल पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि क्या मामले का यह पहलू न्यायोचित था। यह आगे एक तथ्य के रूप में पाया गया कि याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों का रवैया था

यदि यह सी. ई. सी. द्वारा दिखाई गई दूरदर्शिता और संयम के लिए नहीं होता, तो आयोग का काम रुक जाता और आयोग निष्क्रिय हो जाता। यही कारण है कि अदालत ने कहा कि किसी को भी पोस्ट पर आँसू बहाने की आवश्यकता नहीं है

समाप्त कर दिया गया (निर्णय के पैराग्राफ 20,23,24 और 25 के अनुसार)। इसलिए न्यायालय ने राष्ट्रपति की अधिसूचनाओं को बरकरार रखते हुए इसके निर्माण को रद्द कर दिया

पक्ष, आदि, जिस पर याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा काफी निर्भरता रखी गई थी। हम चुनाव आयोग की स्थिति के संबंध में मुख्य विशेषताओं पर पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। हमने प्रावधानों की ओर इशारा किया है

सीईसी, ईसी और आरसी के कार्यकाल, सेवा की शर्तों, वेतन, भत्ते, हटाने योग्य आदि के संबंध में। अकेले सी. ई. सी. और ई. सी. निर्वाचन आयोग का गठन करता है जबकि आर. सी. की नियुक्ति केवल आयोग की सहायता के लिए की जाती है। आर. सी. की नियुक्ति T.N.SESHAN v के बाद की जा सकती है।

चुनाव आयोग से परामर्श करना क्योंकि उनसे अनुच्छेद 324 के खंड (1) द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में उस निकाय की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। यदि ऐसा है तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वे सी. ई. सी. और ई. सी. के बगल में होंगे। यह हमें सीईसी बनाम ईसी की स्थिति के बारे में सवाल पर लाता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सी. ई. सी. को इस स्पष्ट कारण से ई. सी. से बेहतर दर्जा प्राप्त है कि (i) सी. ई. सी. को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान सेवा की शर्तें दी गई हैं जो अध्यादेश से पहले ई. सी. की सेवा की शर्तों के साथ मामला नहीं था, (ii) सी. ई. सी. को सेवा से हटाने के खिलाफ वही संरक्षण दिया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उपलब्ध है, जबकि सी. ई. सी. की सिफारिश पर ई. सी. को हटाया जा सकता है, (iii) सी. ई. सी. की सेवा की शर्तों को उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए पेश नहीं किया जा सकता है या बदला नहीं जा सकता है, (iv) सी. ई. सी. को बहु-सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है और (v) सी. ई. सी. इस तर्क के समर्थन में धनोआ के मामले के पैराग्राफ 10 और 11 में टिप्पणियों पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय सीईसी को चुनाव आयोग की तुलना में उच्च दर्जा प्राप्त है। अवलोकन इस प्रकार पढ़ा गया:

" 10. हालांकि, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तों और पद के कार्यकाल के मामले में एक अंतर किया गया है।

एक ओर मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरी ओर चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों के बीच

अन्य। जबकि सभी की सेवा की शर्तें और पद की अवधि ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे, मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले में संरक्षण दिया जाता है कि उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा की शर्तों में उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा, और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और समान आधारों के अलावा अपने पद से नहीं हटाया जाएगा। ये सुरक्षा न तो चुनाव आयुक्तों के लिए उपलब्ध हैं और न ही क्षेत्रीय आयुक्तों के लिए। उनकी सेवा की शर्तें उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए भी बदल सकती हैं और उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, हालांकि अन्यथा नहीं। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि इन दो मामलों में न केवल चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर नहीं हैं, बल्कि उन्हें क्षेत्रीय

126

यद्यपि पूर्व आयुक्त आयोग का गठन करते हैं

और बाद वाले नहीं करते हैं और केवल कॉम मिशन की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

11. इन विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि यद्यपि अनुच्छेद के खंड (2) में कहा गया है कि आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे -

यदि और जब नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि संविधान के निर्माता चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान दर्जा देना चाहते थे। इसलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त अंतर-पक्षीय रूप से प्रथम प्रतीत नहीं होता है, यानी बराबर के बीच प्रथम, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उच्च पद पर रखा जाना है। शर्तों कि राष्ट्रपति समय की जरूरतों के अनुसार चुनाव आयोग मिशनरियों की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं, कि उनकी सेवा की शर्तें उनके नुकसान के लिए भिन्न हो सकती हैं और वे कर सकते हैं
मुख्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर हटाया जाए

मिशनरी उनके समान दर्जे के होने के खिलाफ लड़ते हैं

मुख्य चुनाव आयुक्त "।

हालांकि यह सच है कि अनुच्छेद 324 की योजना के तहत चुनाव के सभी अधिकारियों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल

आयोग का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा तब तक किया जाना है जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, यह केवल सी. ई. सी. के मामले में है कि खंड (5) का पहला परंतुक यह निर्धारित करता है कि उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें सी. ई. सी. के लाभ के अनुसार नहीं बदला जा सकता है। इस तरह की सुरक्षा ईसी को नहीं दी जाती है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि अध्यादेश के आधार पर वेतन आदि के मामले में सी. ई. सी. और ई. सी. एस. को बराबर रखा गया है। क्या ईसी के लिए इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति सीईसी को ईसी से बेहतर बनाती है? दूसरा आधार हटाने योग्य से संबंधित है। सी. ई. सी. के मामले में उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है, जबकि सी. ई. सी. की सिफारिश पर ई. सी. एस. को हटाया जा सकता है। हालाँकि, यह सीईसी को उच्च दर्जा देने का संकेत नहीं है। ऐसा मानना संविधान के अनुच्छेद 324 की योजना की अनदेखी करना है। यह याद रखना चाहिए कि सी. ई. सी. का उद्देश्य एक स्थायी पदधारी होना है और इसलिए, उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित और संरक्षित करने के लिए, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाना था। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीईसी के बिना चुनाव आयोग नहीं हो सकता है। अन्य ईसी के साथ ऐसा नहीं है। उनका स्थायी T.N.SESHAN v होने का इरादा नहीं है।

पदधारी। अनुच्छेद 324 के खंड (2) से ही पता चलता है कि समय-समय पर ईसीएस की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। इसलिए चीजों की प्रकृति में, उन्हें उस प्रकार की अपरिवर्तनीयता से सम्मानित नहीं किया जा सकता है जो सी. ई. सी. को प्रदान की जाती है। यदि ऐसा करना है तो अनुच्छेद 324 की पूरी योजना में बदलाव करना होगा। इसलिए, चीजों की योजना में, कुछ मामलों में हटाने की शक्ति को बनाए रखना पड़ा। सी. ई. सी. को बाहरी राजनीतिक या कार्यकारी दबावों से अलग रखने के बाद, इस स्वतंत्र पदाधिकारी में अपने ई. सी. और यहां तक कि आर. सी. की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए विश्वास व्यक्त किया गया था कि उन्हें सी. ई. सी. की सिफारिश के अलावा हटाया नहीं जा सकता है। यह संविधान सभा में श्री के. एम. मुंशी के भाषण में पाए गए निम्नलिखित कथन से स्पष्ट होता है जब उन्होंने डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधित मसौदे का समर्थन किया था:

> " हम हर समय चुनाव आयोग की बैठक नहीं कर सकते।
>
> वे पाँच साल कुछ नहीं कर रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त के कर्तव्यों का पालन करने वाला एक पूर्णकालिक अधिकारी बना रहेगा
>
> उसका कार्यालय और दिन-प्रतिदिन काम की देखभाल करना लेकिन जब
>
> देश में बड़े चुनाव होते हैं, या तो प्रांतीय या
>
> केंद्रीय, काम से निपटने के लिए आयोग का विस्तार किया जाना चाहिए।
>
> इसलिए आयोग में और अधिक सदस्यों को जोड़ा जाना चाहिए।
>
> उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने में कोई संदेह नहीं है। इसलिए,
>
> इस हद तक उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। तो कोई कारण नहीं है
>
> यह विश्वास करने के लिए कि ये अस्थायी चुनाव आयुक्त नहीं करेंगे
>
> स्वतंत्रता का आवश्यक उपाय करें "।

चूंकि अन्य निर्वाचन आयोगों का स्थायी रूप से नियुक्त होने का इरादा नहीं था, इसलिए उन्हें सीईसी की अपरिवर्तनीयता सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी।

अधिकारी पदधारी, और इसलिए, उन्हें एक स्वतंत्र सीईसी की सुरक्षात्मक छत्रछाया के तहत रखा गया था। इस मामले का यह पहलू उन विद्वान न्यायाधीशों के ध्यान से बच गया जिन्होंने धनोआ के मामले का फैसला किया। हम भी हैं।

यह विचार कि निर्णय के अनुच्छेद 17 में संविधान के अनुच्छेद 74 और 163 के तहत कार्यपालिका के कामकाज के साथ तुलना सम्मान के साथ, उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है।

अनुच्छेद 324 के खंड (3) के तहत, बहु-सदस्य चुनाव आयोग के मामले में, सी. ई. सी. आयोग के अध्यक्ष के रूप में 'कार्य करेगा'। जैसा कि हमने पहले बताया है, अनुच्छेद 324 में एक स्थायी निकाय की परिकल्पना की गई है जिसकी अध्यक्षता एक स्थायी पदधारी, अर्थात् सीईसी द्वारा की जाएगी। यह तथ्य कि सी. ई. सी. एक स्थायी पदधारी है, उन्हें 128 से अधिक नहीं दे सकता है।

ई. सी. की तुलना में स्थिति इस साधारण कारण से है कि बाद वाले स्थायी रूप से नियुक्त होने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। चूँकि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची तैयार करने आदि के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए अपना एक कर्मचारी होगा, इसलिए उस कर्मचारी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश और मार्गदर्शन में काम करना होगा और इसलिए संविधान निर्माताओं के लिए यह प्रावधान करना उपयुक्त होगा कि क्या चुनाव आयोग एक बहु-सदस्य निकाय है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इससे आयोग की निरंतरता और सुचारू कार्यप्रणाली भी सुनिश्चित होगी।

यह हमें इस सवाल पर लाता है: बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में सी. ई. सी. की क्या भूमिका है? अनुच्छेद 324 में ऐसा नहीं है

इस बिंदु पर कोई भी प्रकाश डालें। संविधान सभा की बहस भी मदद नहीं करती है। हालाँकि अतीत में एक बहु-सदस्य आयोग था, तब कोई परंपरा या प्रक्रियात्मक व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन इसी स्थिति ने धनोआ के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ को अन्य बातों के साथ यह टिप्पणी करने के लिए मजबूर किया कि इसके विपरीत नियमों के अभाव में, एक बहु-सदस्य निकाय के सदस्य अपने अधिकारों, अधिकार और शक्तियों के मामले में हमेशा एक-दूसरे के बराबर नहीं होते हैं और न ही उनकी आवश्यकता होती है। पैराग्राफ 18 में आगे बढ़ते हुए कहा गया था:

" 18. यह एक बहु-सदस्य निकाय में व्यवसाय का लेन-देन करने का एक स्वीकृत नियम है कि जब इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो व्यवसाय को सर्वसम्मति से चलाया जाना चाहिए। इसके विपरीत नियम जैसे कि बहुमत द्वारा निर्णय को विशेष रूप से बहुमत के प्रकार को निर्दिष्ट करके निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या

सरल, विशेष, सभी सदस्यों या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों आदि का। चुनाव आयोग जैसे मामले में, जो केवल एक सलाहकार निकाय नहीं है, बल्कि एक कार्यकारी निकाय है, सभी मामलों में सर्वसम्मत निर्णयों पर जोर देकर अपने कार्यों को जारी रखना मुश्किल है। इसलिए, एक यथार्थवादी दृष्टिकोण की मांग है कि या तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से पहले या उनके साथ-साथ या चुनाव आयोग की कोई नियुक्ति नहीं होने पर, कार्य-निष्पादन की प्रक्रिया को एक कानून या नियम द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

इस तरह की प्रक्रिया के अभाव में मिशनर बनाए जाते हैं। वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

हमें जल्दबाजी में यह जोड़ना होगा कि इस कथन की सटीकता कि एक बहु-सदस्य निकाय में T.N.SESHAN v के अभाव में सर्वसम्मति का नियम प्रबल होगा।

इसके विपरीत व्यक्त प्रावधान को उत्तरदाताओं के वकील-ईसी द्वारा दोगुना कर दिया गया था। उसी समय, भारत संघ और प्रतिस्पर्धा करने वाले निर्वाचन आयोगों के वकील ने तर्क दिया कि अध्यादेश द्वारा प्ररव्यापित किया गया था

राष्ट्रपति ने धनोआ के मामले में व्यक्त किए गए विचार का सख्ती से पालन किया। चर्चा से इस बिंदु तक जो सामने आता है वह यह है कि अनुच्छेद 324 के खंड (1) द्वारा, संविधान निर्माताओं ने देश में सभी चुनावों के संचालन का कार्य एक आयोग को सौंपा, जिसे चुनाव के रूप में संदर्भित किया जाता है।

कमीशन और किसी व्यक्ति के लिए नहीं। यह हो सकता है कि यदि यह एकल-सदस्य निकाय है तो निर्णय सी. ई. सी. द्वारा लिए जाने पड़ सकते हैं लेकिन फिर भी वे निर्णय चुनाव आयोग के होंगे। वे चुनाव आयोग के उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे, न कि व्यक्ति के। व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना और चुनाव आयोग को ग्रहण करना गलत होगा। कोई भी उस संस्था से ऊपर नहीं हो सकता है जिसकी उसे सेवा करनी है। वह केवल संस्था का सृजन है, वह तभी अस्तित्व में रह सकता है जब संस्था मौजूद हो। व्यक्ति को संस्था से अधिक शक्तिशाली के रूप में पेश करना एक गंभीर गलती होगी। इसलिए, भले ही चुनाव आयोग एक एकल-सदस्य निकाय हो, सी. ई. सी. केवल उस निकाय का एक पदाधिकारी है; इसे अलग तरीके से कहें तो, आयोग का अहंकार है और इससे अधिक नहीं। और यदि यह एक बहु-सदस्य निकाय है तो सी. ई. सी. इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य है। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार 'अध्यक्ष' का अर्थ है अध्यक्षता करने के लिए चुना गया व्यक्ति।

बैठकें, उदाहरण के लिए, वह जो निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 6ठे संस्करण, पृष्ठ 230 में, एक ही अभिव्यक्ति को एक विधानसभा, सार्वजनिक बैठक, सम्मेलन, विचारशील या विधायी निकाय, निदेशक मंडल, समिति, आदि के पीठासीन अधिकारी को दिए गए नाम के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी तरह के अर्थ बैलेन्टाइन लॉ डिक्शनरी, तीसरे संस्करण, पृष्ठ 189-190, वेबस्टर्स न्यू ट्वेंटिएथ सेंचुरी डिक्शनरी, अनएब्रिज्ड, दूसरा संस्करण, पृष्ठ 29, और आयर्स जुडिशियल डिक्शनरी, 11वें संस्करण, पृष्ठ 238 में उस अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अतः सभापति का कार्य बैठकों की अध्यक्षता करना, व्यवस्था बनाए रखना होगा।

दिन के व्यवसाय का संचालन करें, सुनिश्चित करें कि सटीक निर्णय लिए गए हैं और सही ढंग से दर्ज किए गए हैं और सुचारू लेनदेन या व्यवसाय के लिए आवश्यक सब कुछ करें। इस कार्यालय की प्रकृति और कर्तव्य इस आधार पर भिन्न हो सकते हैं -

लेन-देन किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति लेकिन कुल मिलाकर ये अध्यक्ष के कार्य होंगे। उसे अपनी अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में इस तरह से आचरण करना चाहिए कि वह आयोग पर अपने सहयोगियों का विश्वास जीतने और उन्हें अपने साथ ले जाने में सक्षम हो। यह एक अध्यक्ष को मिल सकता है

यदि वह सोचता है कि आयोग के अन्य सदस्य उसके अधीनस्थ हैं तो इसे प्राप्त करना मुश्किल है।

130

सायन अनिवार्य रूप से प्रशासनिक हैं लेकिन कुछ निर्णयात्मक और विधायी कार्य भी हैं। चुनाव आयोग को कुछ नीतियां निर्धारित करनी होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लेना होता है जो प्रशासन के नियमित मामलों से अलग होते हैं और निर्णय भी लेना होता है

कुछ विवाद, जैसे, प्रतीकों के आवंटन से संबंधित विवाद। इसलिए, प्रशासनिक कार्यों के अलावा इसे अर्ध प्रदर्शन करने के लिए भी कहा जा सकता है।

न्यायिक कर्तव्यों को निभाना और अधीनस्थ कानून बनाने के कार्यों को भी करना। एम. एस. गिल बनाम देखें। मुख्य चुनाव आयुक्त, [1978] 2 एससीआर 272। हमें इस मामले पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि चुनाव आयोग एक

सार्वजनिक कार्य। जैसा कि पहले बताया गया है, अनुच्छेद 324 की योजना में स्पष्ट रूप से एक बहु-सदस्य निकाय की परिकल्पना की गई है जिसमें सीईसी और ईसी शामिल हैं। आर. सी. को आयोग की सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यदि ऐसा है तो ईसी। आर. सी. के बराबर नहीं रखा जा सकता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, निर्वाचन आयोग आर. सी. के विपरीत चुनाव आयोग का हिस्सा हैं। इसलिए, उनकी भूमिका आर. सी. की तुलना में अधिक है। यदि वे आयोग का हिस्सा हैं तो यह मानना तर्कसंगत है कि निर्णय लेने में उनकी राय होनी चाहिए। यदि सी. ई. सी. को इस अर्थ में श्रेष्ठ माना जाता है कि यह शब्द अंतिम है, तो वह ई. सी. को गैर-कार्यात्मक या सजावटी बना देगा। इस तरह के इरादे को अनुच्छेद 324 से स्पष्ट करना मुश्किल है और न ही हम इसका श्रेय संविधान निर्माताओं को दे सकते हैं। हमें इस तर्क को अस्वीकार करना चाहिए कि निर्वाचन आयोग का कार्य केवल सीईसी को सलाह देना है।

हमने सी. ई. सी. और ई. सी. की स्थिति के बीच अनुच्छेद 324 से अलग विशेषताओं की ओर इशारा किया है। अनिवार्य रूप से चुनाव आयोग में उनके कार्यकाल के कारण कुछ मतभेद मौजूद हैं। हमने समझाया है कि ईसी के मामले में हटाने योग्य खंड अलग क्यों होना चाहिए। वेतन आदि में भिन्नता एक निर्धारक कारक नहीं हो सकता है अन्यथा यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दोलन करेगा कि

कार्यपालिका या विधायिका को अनुच्छेद 324 के खंड (5) के तहत सेवा की शर्तें तय करनी होती हैं। एकमात्र विशिष्टता जो पक्ष लेने के लिए बनी रहती है, वह यह है कि सी. ई. सी. के मामले में उनकी सेवा की शर्तों को उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है, जबकि ई. सी. के मामले में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि पद अस्थायी हैं। लेकिन भले ही ऐसा न हो, लेकिन यह विशेषता अकेले हमें इस निष्कर्ष पर नहीं ले जा सकती है कि सभी मामलों में अंतिम शब्द सीईसी के पास है। इस तरह का दृष्टिकोण निर्वाचन आयोग की स्थिति को केवल एक सलाहकार के रूप में प्रस्तुत करेगा जो अनुच्छेद 324 की योजना से नहीं निकलता है।

जैसा कि पहले बताया गया है, न तो अनुच्छेद 324 और न ही कोई अन्य प्रावधान

संविधान स्पष्ट रूप से बताता है कि कैसे एक बहु-सदस्य चुनाव आयोग अपना कार्य करेगा और न ही इस संबंध में कोई परंपरा विकसित की गई है। यही कारण है कि धनोआ के मामले में इस अदालत ने सोचा कि इस अंतर को एक उचित वैधानिक प्रावधान द्वारा भरा जा सकता है। उक्त निर्णय में उस संबंध में अवलोकन से एक संकेत लेते हुए, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया जिसके तहत अधिनियम में धारा 9 और 10 वाला एक नया अध्याय जोड़ा गया था जो यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग अपने कामकाज को कैसे चलाएगा। धारा 9 में केवल यह कहा गया है कि आयोग का कार्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। धारा 10 में तीन उप-खंड हैं। उप-धारा (1) में कहा गया है कि चुनाव आयोग सर्वसम्मत निर्णय से अपने व्यवसाय के लेन-देन की प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है।

सी. ई. सी. और ई. सी. के बीच अपने व्यवसाय के आवंटन के लिए। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि विधायिका ने इसे चुनाव आयोग पर छोड़ दिया है

सर्वसम्मत निर्णय द्वारा दोनों मामलों को अंतिम रूप दें। उप-धारा (2) में कहा गया है कि उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर अन्य सभी व्यवसाय भी जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से किए जाएंगे। यह केवल तभी होता है जब सी. ई. सी. और ई. सी. अपने व्यवसाय के संबंध में सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं कि निर्णय बहुमत से होना चाहिए। यह महसूस किया जाना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने इस बारे में चुप रहना पसंद किया कि चुनाव आयोग अपने कार्यों को किस तरह से करेगा, संभवतः इसलिए कि उन्होंने आयोग को चलाने के लिए अपने दिमाग में कर्मियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए इसके लिए प्रावधान करना अनावश्यक और शायद अनुचित भी समझा। वे सी. ई. सी. और उनके सहयोगियों की दूरदर्शिता और विवेक पर निर्भर रहे होंगे। अतीत के कड़वे अनुभव, जिसके लिए धनोआ के मामले में एक संदर्भ दिया गया है, ने विधायी हस्तक्षेप को आवश्यक बना दिया जब यह भी महसूस किया गया कि एक बहु-सदस्य निकाय आवश्यक था। यह अभी तक है उप-धारा (1) और (2) में यह आशा व्यक्त की गई कि आयोग एक स्वर में निर्णय लेने में सक्षम होगा। लेकिन अगर उस उम्मीद को झुठलाया जाता है तो बहुमत का नियम लागू होना चाहिए। यही अधिनियम की धारा 10 का उद्देश्य है। यह निवेदन कि उक्त दो धाराएं अनुच्छेद 324 की योजना के साथ असंगत हैं क्योंकि वे दोनों को वस्तुतः नष्ट कर देती हैं।

सुरक्षा उपाय, अर्थात् (i) सी. ई. सी. की अपरिवर्तनीयता और (ii) इस ए. पी. पॉइंटमेंट के बाद उसके नुकसान के लिए सेवा शर्तों में भिन्नता के खिलाफ निषेध, बर्फ में कटौती नहीं करता है। सबसे पहले, प्रस्तुतिकरण इस आधार पर आगे बढ़ता है कि अन्य दो ईसी सीईसी को प्रस्तुत करने के लिए हाथ मिलाएंगे। गैर-कार्यात्मक, एक आधार जो आवश्यक नहीं है। यह अपने सहयोगियों को अपने साथ ले जाने के लिए सी. ई. सी. के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है।

प्रत्येक बहु-सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1995] में समर्थन। 2 एस सी आर।

132

सदस्य आयोग यह प्रमुख व्यक्ति के नेतृत्व की गुणवत्ता है

शरीर जो मायने रखता है। दूसरा, तर्क का अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि अकेले सी. ई. सी. के पास निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, जिसे, जैसा कि पहले बताया गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह ई. सी. के अस्तित्व को सजावटी बनाता है। इसके अलावा, दोनों सुरक्षा उपायों और धारा 9 और 10 के बीच कोई वैध संबंध नहीं है; वास्तव में प्रस्तुत करना इस तर्क की पुनरावृत्ति है कि एक बहु-सदस्य आयोग काम नहीं कर सकता है, कि यह पूरी तरह से अव्यवहारिक होगा और संविधान निर्माताओं ने इसके लिए प्रावधान करने में गलती की थी। संक्षेप में कहें तो तर्क इस ओर जाता है; बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग के विचार को अपने दिमाग से मिटा दें या अन्यथा इसे विशेष रूप से दिया जाए। सी. ई. सी. को निर्णय लेने की शक्ति। हमें डर है कि इस तरह का रवैया लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए अपमानजनक नहीं है। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के पृष्ठ 657 पर फुट नोट 6, चौथा संस्करण (री-इश्यू), वॉल्यूम। 7 (1) स्थिति:

" यह सिद्धांत लंबे समय से स्थापित किया गया है कि एक निगम या निकाय की इच्छा केवल उसके सिद्धांतों के पूरे या बहुमत से व्यक्त की जा सकती है, और बहुमत के कार्य को पूरे का कार्य माना जाता है। (सभाओं के कानून और व्यवहार पर शकील्टन को देखें,

आठवां संस्करण, एजी का संकलन, पृष्ठ 116) "

इसी सिद्धांत को ग्रिंडले बनाम में दोहराया गया था। बार्कर, 126 अंग्रेजी

879 पर रिपोर्टर 875 & 882. हम इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों से गुजरना आवश्यक नहीं समझते हैं।

यह तर्क कि विवादित प्रावधान संविधान के साथ धोखाधड़ी करते हैं क्योंकि वे संविधान को हराने के लिए बनाए गए और गणना किए गए हैं।

चुनाव आयोग होने का उद्देश्य ही सवाल पूछना है। जबकि लोकतंत्र में प्रत्येक सही सोचने वाले नागरिक को चिंतित होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता के बारे में यह न्यायालय उसी के बारे में कम चिंतित नहीं है जैसा कि निर्णयों की एक श्रृंखला से स्पष्ट होगा-यह मुश्किल है

इस अंतर्निहित सुझाव को साझा करने के लिए कि निर्वाचन आयोग इसके बारे में उतना चिंतित नहीं होंगे। और यह कहने के लिए कि सी. ई. सी. को अपमान सहना होगा

दो सिविल सेवकों द्वारा ओवरराइड किया जाना इस तथ्य को नजरअंदाज करना है कि वर्तमान सीईसी स्वयं सीईसी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले एक सिविल सेवक थे।

चुनाव आयोग एकमात्र निकाय नहीं है जो एक बहुस्तरीय निकाय है।

सदस्य निकाय। संविधान अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए भी प्रावधान करता है। बहु-सदस्य निकाय होना। उदाहरण के लिए, लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 325 संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 316 एक बहु-सदस्य T.N.SESHAN v पर विचार करता है।

एक अध्यक्ष के साथ निकाय। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हैं। इसी तरह संविधान के तहत कुछ अन्य बहु-सदस्य आयोगों या संसदीय समितियों की स्थापना के प्रावधान भी थे। ये भी बहुमत के नियम से काम करते हैं और इसलिए हमें इस व्यापक तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि एक बहु-सदस्य आयोग अव्यवहारिक है। यह सब अध्यक्ष और उसके रवैये पर निर्भर करता है।

सदस्य। यदि वे सहयोग से काम करते हैं, एक-दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं और सम्मान करते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन यदि वे शुरू से ही विपरीत दिशा में जाने का फैसला करते हैं, तो वे अपने आचरण से आयोग को अव्यवहारिक बना देंगे और इस तरह प्रणाली को विफल कर देंगे।

यह हमें दुर्भावना के सवाल पर ले जाता है। यह दो भागों में है। पहला भाग अध्यादेश से पहले की घटनाओं से संबंधित है और दूसरा

भाग से भाग तक-अध्यादेश और अधिसूचना कार्यक्रम। पहले भाग में सी. ई. सी. का तर्क है कि चूंकि, उनकी नियुक्ति के बाद, उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए थे और कुछ चुनावों को स्थगित करने के लिए विवश थे जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल यानी राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) के कुछ नेताओं के भाग्य का फैसला करने के लिए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें काफी परेशान किया था। आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से पालन पर उनके आग्रह ने सत्तारूढ़ दल की गणना को भी बाधित कर दिया है। उनके अनुसार, उन्होंने हरियाणा के कालका विधानसभा क्षेत्र में चुनाव स्थगित कर दिए थे, क्योंकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंधित हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था। इसलिए भी उन्होंने त्रिपुरा राज्य में चुनाव स्थगित कर दिए थे, जिसके कारण अंततः केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंधित मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। श्री शरद पवार और श्री प्रणब मुखर्जी से जुड़े उपचुनावों के स्थगित होने से भी जनता परेशान थी।

उक्त पार्टी की गणना के अनुसार, उन्होंने तमिलनाडु के अनिपेट विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव स्थगित कर दिया था, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव की पूर्व संध्या पर कुछ परियोजनाओं की घोषणा करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। श्री संतोष मोहन देब, केंद्रीय मंत्री,

सत्तारूढ़ दल के लिए, यह भी परेशान था क्योंकि सीईसी ने उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जो उनकी चुनाव बैठकों में मौजूद पाए गए थे। सत्तारूढ़ दल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों की घोषणा करने के उनके फैसले से भी नाखुश था क्योंकि पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। सी. ई. सी. के अनुसार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1995] एस. यू. पी. पी. द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से किए गए अनुरोध को भी ठुकरा दिया था।

134

दिल्ली चुनाव को स्थगित करने के लिए उक्त पार्टी। उनके अनुसार, केंद्र में उक्त पक्ष द्वारा उनके पास दूत भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, श्री मोती लाल वोहरा के आचरण के बारे में गंभीर आपत्ति भी जताई। चूंकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल उन पर हावी होने के अपने सभी प्रयासों में विफल रहा, इसलिए उसने चुनाव आयोग को बदलने का फैसला किया।

एक बहु-सदस्य निकाय में मिशन और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के बाद, दोनों निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति के लिए विवादित अधिसूचनाएं जारी की गईं। सी. ई. सी. के पुणे में रहते हुए यह सब जिस असाधारण जल्दबाजी में किया गया था और जिस तात्कालिकता के साथ नियुक्त किए गए लोगों में से एक श्री एम. एस. गिल को एक विशेष विमान द्वारा दिल्ली बुलाया गया था, उसने सत्तारूढ़ दल की ओर से दो नव नियुक्त निर्वाचन आयोगों को स्थापित करने की उत्सुकता को धोखा दिया। सीईसी ने रिट याचिका के पैराग्राफ 18 (सी) से (एफ) और (जी) में 11 अक्टूबर, 1993 की बैठक में हुई नियुक्ति के बाद की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उनके अनुसार, अध्यादेश और अधिसूचना जारी करके सत्तारूढ़ दल अप्रत्यक्ष रूप से वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो वह प्रत्यक्ष रूप से हासिल नहीं कर सका। ये, संक्षेप में, व्यापक गणनाएँ हैं जिनके आधार पर तर्क दिया जाता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल उन्हें हटाने के लिए उत्सुक था। भारत संघ की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि यह आरोप कि एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया गया था, अर्थात्, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए, पूरी तरह से गलत है क्योंकि यह एक ज्ञात तथ्य है कि एक बहु-सदस्य आयोग की मांग समय-समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने उठाई गई थी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने 1972 में एक बहु-सदस्य निकाय की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी की ओर से नियुक्त तर्कुंडे समिति ने भी अगस्त, 1974 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में एक बहु-सदस्य चुनाव आयोग का समर्थन किया था। इसी तरह, जनता दल सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव सुधार समिति ने मई, 1990 में अपनी रिपोर्ट में तीन सदस्यीय चुनाव आयोग का समर्थन किया था। संसद के विभिन्न सदस्य

विभिन्न राजनीतिक रंगों ने भी समय-समय पर इसी तरह की मांग उठाई थी। विभिन्न राज्यों के महा-अधिवक्ताओं ने 26 सितंबर, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में इसी तरह की मांग की थी। इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं था कि वर्तमान सीईसी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग के गठन का निर्णय अचानक दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिया गया था। आरोप है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि केंद्र में सत्तारूढ़ दल T.N.SESHAN v से नाराज था।

किसी न किसी आधार पर चुनाव स्थगित करने में सी. ई. सी. के रवैये से इनकार किया जाता है। बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग के गठन का मुद्दा एक जीवंत मुद्दा था और इसे विभिन्न मंचों पर खारिज कर दिया गया था और यहां तक कि धनोआ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी संकेत दिया था कि विशाल विवेकाधीन शक्तियां, जिनमें वस्तुत: कोई नियंत्रण और संतुलन नहीं है, किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं छोड़ी जानी चाहिए और यह वांछनीय था कि एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, यह जनहित में था कि विचाराधीन अध्यादेश जारी किया गया था और सीईसी के साथ जुड़ने के लिए दो ईसी नियुक्त किए गए थे। प्रतिनिधि का कहना है कि यह एक प्रामाणिक अभ्यास था और यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि सीईसी जैसे एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने आरोप लगाया था कि ईसीएस में से एक को नियुक्त किया गया था क्योंकि वह प्रधानमंत्री का करीबी दोस्त था, एक आरोप जो निराधार था। इसलिए इस बात से इनकार किया जाता है कि दो निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करने वाली ओर दिनेंस और बाद की अधिसूचनाओं का उद्देश्य सीईसी को दरकिनार करना और उनके अधिकार को कम करना था। सरकार ने पहले की रिपोर्टों और टिप्पणियों का ईमानदारी से पालन किया धनोआ का मामला जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि धारा 9 और 10 में कोई बुराई नहीं है जैसा कि सी. ई. सी. द्वारा आरोप लगाया गया है। दोनों निर्वाचन आयोगों ने इन आरोपों से इनकार करते हुए अपना जवाबी हलफनामा भी दायर किया है। श्री जी. वी. जी. कृष्णमूर्ति, सी. ई. सी. में प्रतिवादी संख्या 3

याचिका में कहा गया है कि सी. ई. सी. ने अभूतपूर्व मांगें की थीं, उदाहरण के लिए, (i) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होने के लिए, और सरकार पर दबाव डाला था कि उन्हें वरीयता के वारंट में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ स्थान दिया जाए, (ii) अदालत की अवमानना की शक्तियां चुनाव आयोग को प्रदान की जाएं, (iii) सी. ई. सी. ने जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. एम. मीर की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य के रूप में बैठकों में भाग लेने से इनकार कर दिया था, इस आधार पर कि उनका पद अधिक था, उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर माना गया था, (iv) सी. ई. सी. को इसके लिए छूट दी जाए। न्यायालय में सोनल उपस्थिति, (v) जहां तक इसके कर्मचारियों आदि का संबंध है, चुनाव आयोग को यू. पी. एस. सी. के दायरे से छूट दी जाए।

विद्वान महान्यायवादी ने बताया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा विधायी शक्ति के प्रयोग के लिए किसी भी दुर्भावना को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है

संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। उन्होंने आगे बताया कि

संविधान के अनुच्छेद 324 (2) की स्पष्ट भाषा के संबंध में, चुनाव आयोग का विस्तार करना पूरी तरह से उचित था। कानून की सीमा में परिवर्तन करना। यह सवाल कि क्या सीईसी के अलावा अन्य ईसी की नियुक्ति करना आवश्यक है, सरकार को 136 पर निर्णय लेना है

और यह न्यायोचित मामला नहीं है। पिछले कई वर्षों से एक बहु-सदस्य आयोग की मांग की जा रही थी और केवल इसलिए कि एक अध्यादेश के माध्यम से क़ानून में संशोधन करने का निर्णय लिया गया था, यह निष्कर्ष निकालना स्वीकार्य नहीं है कि निर्णय द्वेष से प्रेरित था। अंत में यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 324 में कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया गया है कि ईसीएस की नियुक्ति से पहले सीईसी से परामर्श किया जाएगा। उस ओर से एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि दो निर्वाचन आयोगों की नियुक्तियों से पहले सीईसी से परामर्श करने में विफलता नियुक्ति को दूषित करती है। हस्तक्षेप करने वालों में से एक, 1993 के एस. एल. पी. संख्या 16940 के याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं, जिसमें उनका समर्थन करते हुए

बहु-सदस्य आयोग के गठन के लिए कार्रवाई करते हुए, उन्होंने सी. ई. सी. के काम करने की शैली की आलोचना की है और तर्क दिया है कि उनके कार्यों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के बजाय, लोगों के साथ-साथ व्यवस्था के लिए भी कठिनाइयाँ पैदा की हैं। यह बताया गया है कि सी. ई. सी. द्वारा कई जल्दबाजी में निर्णय लिए गए थे-इस संभावना पर कि वे एक साथ पास हो जाएंगे, लेकिन जब अदालत में चुनौती दी गई तो वह उनका समर्थन करने में विफल रहे और अपने आदेशों को वापस लेने के लिए सहमत हो गए। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान सी. ई. सी. के कार्य करने की शैली ही एक बहु-सदस्य आयोग के गठन के लिए पर्याप्त कारण है ताकि विभिन्न संस्थानों के लिए संविधान द्वारा प्रदान की गई नियंत्रण और संतुलन प्रणाली उचित व्यवस्था सुनिश्चित कर सके।

निर्णय लेना।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब संविधान बनाया गया था तो संविधान निर्माताओं ने एक स्थायी निकाय का नेतृत्व करना आवश्यक समझा था

सीईसी द्वारा। शायद काम की मात्रा और उसकी जटिलता को एक एकल-सदस्य निकाय द्वारा प्रबंधित किया जा सकता था। साथ ही यह महसूस किया गया कि समय बीतने के साथ एक बहु-सदस्य निकाय होना आवश्यक हो सकता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 324 के खंड (2) में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। ऐसा लगता है कि लगभग दो दशकों तक एक बहु-सदस्य निकाय की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी। लेकिन इस मुद्दे को उठाया गया और संयुक्त समिति द्वारा विचार किया गया जिसने 1972 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। चूंकि उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए एक गैर-सरकारी संगठन, सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसने अगस्त 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन दोनों निकायों ने एक बहु-सदस्य आयोग का समर्थन किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और एक विराम के बाद, जब जनता दल सत्ता में आया, तो एक समिति नियुक्त की गई जिसने मई 1990 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस समिति ने एक बहु-सदस्य निकाय का भी समर्थन किया। इससे पहले, 1989 में एक T.N.SESHAN v।

बहु-सदस्य आयोग का गठन किया गया था लेकिन हम इसके भाग्य को जानते हैं (धनोआ का मामला देखें)। लेकिन इस मुद्दे को नहीं छोड़ा गया और संसद सदस्यों से अलग-अलग रंगों की मांगें आती रहीं। भारत संघ के काउंटर में इनका उल्लेख किया गया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विचार अचानक एक थैले से निकाला गया था। यह मानते हुए कि वर्तमान सी. ई. सी. ने कुछ निर्णय लिए थे जो सत्तारूढ़ दल के रूप में स्पष्ट नहीं थे केंद्र, जैसा कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति नहीं है कि निर्वाचन आयोगों की अध्यादेश नियुक्तियों का कारण यही था। यदि इस तरह की सांठगांठ को तूल देना है, तो सी. ई. सी. एक बहु-सदस्य आयोग के लिए कदम को दूर रखने के लिए सत्तारूढ़ दल के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेगा। हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि एक बहु-सदस्य आयोग के गठन का निर्णय द्वेष से प्रेरित था। इसलिए, भले ही द्वेष की वकालत करने की अनुमति नहीं है, हमने विवाद की जांच की है और इसमें कोई योग्यता नहीं देखते हैं। यह सोचना गलत है कि दोनों निर्वाचन आयोग लचीले व्यक्ति थे जिन्हें सीईसी की स्वतंत्रता को कम करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ नियुक्त किया जा रहा था।

हम संयोग से उल्लेख कर सकते हैं कि सी. ई. सी. द्वारा समय-समय पर अंतिम समय में चुनाव स्थगित करने के लिए लिए गए निर्णय, जिनका उन्होंने अपनी याचिका में उल्लेख किया है, ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सीईसी उनका उपयोग अपने इस तर्क की नींव रखने के लिए करता है कि पूरी कवायद दुर्भावनापूर्ण थी। उनके कुछ अन्य फैसले इतने अस्थिर थे कि अदालत में परीक्षण किए जाने पर वे उनका समर्थन नहीं कर सके। कई बार उनके सार्वजनिक बयान इतने अपमानजनक थे कि इस अदालत को उन्हें एक से अधिक अवसरों पर संयम बरतने के लिए आगाह करना पड़ा। यह दिया गया है

यह धारणा कि वह अपनी छवि पेश करने के लिए उत्सुक थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह अक्सर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं और टेलीविजन पर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, यदि सरकार सोचती है कि एक बहु-सदस्य निकाय वांछनीय है, तो सरकार निश्चित रूप से गलत नहीं थी और इसकी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। बाद की घटनाओं से पता चलता है कि सरकार एक बहु-सदस्य आयोग बनाने में पूरी तरह से उचित थी। सी. ई. सी. को टेलीविजन और समाचार पत्र में एक विज्ञापन में देखा गया है। विज्ञापन। सी. ई. सी. ने प्रेस को संबोधित किया है और बताया गया है कि वह अपने कार्यकाल के शेष का उपयोग एक राजनीतिक दल बनाने के लिए करेंगे।

भ्रष्टाचार और इस तरह के [संडे टाइम्स, (बॉम्बे) दिनांक 25 जून, 1995 पृष्ठ 28] से लड़ने के लिए। उनके निर्णयों के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकते हैं यदि यह संदेह है कि संविधान के अनुच्छेद 319 जैसे किसी भी प्रावधान के अभाव में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। सी. ई. सी. है, यह दिखाई देगा, शिष्टाचार और विवेक की भावना से पूरी तरह से अनजान है कि उसके उच्च पद की आवश्यकता है, भले ही कारण प्रशंसनीय हो।

यह हमें विधायी क्षमता के सवाल पर ले जाता है। इसका कारण यह है कि चूंकि अनुच्छेद 324 मौन है, इसलिए संसद आयोग से अपेक्षा करती है कि वह स्वयं अपने व्यवसाय के लेन-देन के लिए अपनी प्रक्रिया विकसित करे और चूंकि सी. ई. सी. आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का भंडार था जो उसकी गतिविधि के दायरे में आता है, इसलिए उसने अपने व्यवसाय के लेन-देन के लिए किसी भी प्रक्रिया को शामिल करने की आवश्यकता नहीं देखी। यदि चुनाव आयोग किसी भी समय इसकी आवश्यकता देखता है, तो वह स्वयं अपनी प्रक्रिया विकसित करेगा लेकिन संसद ऐसा नहीं कर सकती है और इसलिए धारा 9 और 10 असंवैधानिक हैं। कला के खंड (2) और (5) द्वारा विशेष रूप से अनुमत विधान को छोड़कर। 324 और संविधान के अनुच्छेद 327 और 328, भाग XV में किसी अन्य मामले पर संसद द्वारा कानून की परिकल्पना नहीं की गई है और इसलिए विवादित विधान असंवैधानिक है। अब शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 324 के दोनों खंड (2) और (5) निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति के लिए और उनके लिए एक क़ानून पर विचार करते हैं।

अनुसूची. यह प्रविष्टि "संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव; चुनाव आयोग" को संदर्भित करती है। यदि, जैसा कि तर्क दिया गया है, इस प्रविष्टि का दायरा संबंधित है और अनुच्छेद 324 के खंड (2) और (5) और केवल अनुच्छेद 327 और 328 तक ही सीमित है, तो यह केवल तानाशाही होगी। यदि यह तर्क कि केवल सी. ई. सी. के पास निर्णायक शक्ति है, स्वीकार नहीं किया जाता है और हमने इसे स्वीकार नहीं किया है, और यह भी माना जाता है कि सामान्य नियम सर्वसम्मति का है, तो धारा 10 की उप-धारा (1) और (2) में सर्वसम्मति का प्रावधान है। यह केवल तभी है जब कोई सर्वसम्मति नहीं है कि बहुमत उप-धारा (3) के तहत आता है। इसलिए, भले ही हम यह मान लें कि अकेले आयोग यह निर्धारित करने में सक्षम था कि यह कैसे किया जाए।

अपने व्यवसाय का लेन-देन करेगा, उसे उसी पैटर्न का पालन करना होगा

जैसा कि धारा 10 में बताया गया है। इसलिए हम इस तर्क को भी उचित नहीं समझते हैं।

हम यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें धनोआ के मामले के अनुपात को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। जहां आवश्यकता पड़ी, हमने इसे स्पष्ट रूप से मंजूरी दे दी है।

T.N.SESHAN v. यू. ओ. आई. [अहमदिया, जे. जे.

139

जिन मामलों के लिए हमें विज्ञापन देना चाहिए, उनमें से एक सवाल है

एक व्यक्ति की स्थिति जिसकी सेवा की शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान हैं। अपने मामले का समर्थन करने के लिए इस पहलू पर सी. ई. सी. द्वारा रखी गई निर्भरता को देखते हुए यह आवश्यक लगता है। तत्काल मामले में सी. ई. सी. की कुछ सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान हैं, अर्थात् (i) यह प्रावधान कि उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समान तरीके से और समान आधारों पर और (ii) उनकी सेवाओं की शर्तों में नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा। जहाँ तक पहले का संबंध है, अनुच्छेद 124 (4) के प्रावधानों को दोहराने के बजाय, इस प्रारूपक ने इसे संदर्भ द्वारा शामिल किया है। दूसरा प्रावधान अनुच्छेद 125 (2) के प्रावधान के समान है। लेकिन क्या यह सीईसी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा प्रदान करता है? 23 जुलाई, 1992 को तत्कालीन गृह सचिव श्री गोडबोले को संबोधित डी. ओ. संख्या 193/34/92 से ऐसा प्रतीत होता है कि सी. ई. सी. ने सुझाव दिया था कि वरीयता के वारंट में सी. ई. सी. की स्थिति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को उन्होंने दिसंबर 1991 में प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में उठाया था। 25 जुलाई, 1992 के श्री गोडबोले के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि सी. ई. सी. चाहते थे कि उन्हें वरीयता के वारंट में नंबर 9 पर रखा जाए, जिस पद पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। श्री गोडबोले के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन यह

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारत के महान्यायवादी के साथ सीईसी की स्थिति को No.11 पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया।

भारत। हालाँकि, इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि सीईसी और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इसके बाद No.9A पर रखा गया था। हमारे अनुरोध पर विद्वान महान्यायवादी ने हमारे सामने वरीयता का संशोधित वारंट रखा जिससे पता चला कि सी. ई. सी. ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ नंबर 9ए की स्थिति का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का दर्जा बनाए रखना राष्ट्रीय हित में अत्यधिक वांछनीय है। हम इसका उल्लेख करते हैं क्योंकि हाल ही में हम पाते हैं कि

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ अन्य मंचों के दावा समीकरण से संबंधित कार्मिक केवल इसलिए कि उन न्यायालयों द्वारा पहले उल्लिखित कुछ क्षेत्राधिकार उन्हें संवैधानिक और वैधानिक अधिकारियों के बीच अंतर को महसूस नहीं करते हुए हस्तांतरित किए जाते हैं। हम सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं कि उसे समकक्षता प्रदान नहीं करनी चाहिए या वरीयता के वारंट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अगर इससे उच्च पद की स्थिति प्रभावित होने की संभावना है। न्यायालय और

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, हालांकि मांग पर जोर देना, पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार मांगे बिना हो सकता है।

कि सी. ई. सी. के विद्वान वकील श्री जी. रामास्वामी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि सी. ई. सी. वैध रूप से सर्वोच्च के साथ बराबरी का दावा नहीं कर सकता है।

न्यायालय के न्यायाधीश। हम आशा करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और आवश्यक कदम उठाएगी।

हम जानबूझकर अप्रिय आदान-प्रदान में जाने से बच गए हैं

जो सी. ई. सी. के कक्ष में 11 अक्टूबर, 1993 को हुआ था, जिसका संदर्भ सी. ई. सी. द्वारा उनके अनुच्छेद 18 (सी से एफ और जी) में दिया गया है।

याचिका। श्री कृष्णमूर्ति ने इन आरोपों का खंडन किया है और श्री गिल सीईसी का समर्थन नहीं करते हैं जब वे कहते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। हालाँकि इन आरोपों और जवाबी आरोपों ने प्रेस में अपना रास्ता बना लिया, लेकिन हमें नहीं लगता कि सीईसी और श्री कृष्णमूर्ति दोनों को खराब रोशनी में दिखाने के अलावा सार्वजनिक रूप से गंदे लिनन को धोने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा। सी. ई. सी. और ई. सी. उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं। उनके पास सिविल सेवकों के रूप में कई वर्षों का अनुभव है। इन सभी ने विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदार पदों पर कार्य किया है। यह अफ़सोस की बात है कि उन्होंने एक टीम के रूप में काम करने की कोशिश नहीं की। श्री गिल द्वारा अन्य दोनों को अतीत को भूलने और काम के साथ आगे बढ़ने के लिए मनाने के प्रयास बहरे कानों पर गिर गए। दुर्भाग्य से, संदेह और अविश्वास उन पर हावी हो गया। हम आशा करते हैं कि वे आपसी सम्मान और आत्मविश्वास की एक स्वच्छ स्थिति की शुरुआत को भूल जाएंगे और उन्हें सौंपे गए कार्य को खेल भावना के साथ जारी रखेंगे और इस तथ्य को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस महान देश के लोग उन्हें उम्मीद के साथ देख रहे हैं। लोगों और देश की खातिर हम उम्मीद करते हैं कि वे अपने अहंकार को छोड़ेंगे और सौहार्द की भावना से काम करेंगे।

परिणामस्वरूप, हम विवादित अध्यादेश (अब अधिनियम 4) को बरकरार रखते हैं।

1994) पूरी तरह से। हम 1 अक्टूबर, 1993 की दो विवादित अधिसूचनाओं को भी बरकरार रखते हैं। इसलिए, रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। 15 नवंबर, 1993 का अंतरिम आदेश खाली हो जाएगा। यदि, जैसा कि बताया गया है, वर्तमान सी. ई. सी. श्री बग्गा के प्रभारी कार्यालय को छोड़कर छुट्टी पर चले गए हैं, तो श्री बग्गा सी. ई. सी. के फिर से काम शुरू करने तक श्री गिल को तुरंत कार्यभार सौंप देंगे। आई. ए. का निपटारा कर दिया जाएगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम पक्षों को अपनी लागत वहन करने का निर्देश देते हैं। यदि सी. ई. सी. ने अपनी याचिका का खर्च अपने कोष से वहन किया है।

चुनाव आयोग, अन्य दो निर्वाचन आयोग इसी के हकदार होंगे।

एक ही स्रोत।

याचिका

एं खारिज कर दी गईं।

टी. डब्ल्यू.